(ग) देश ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पहले ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। फिर भी विभिन्न फसलों में विकसित और/विकास की जा रही बेहतर किस्मों और संकर किस्मों से यह आशा की जाती है कि इनसे वर्ष 2000 ई. तक खाद्यान्नों की और अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी ।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् बीज मिनिकिट प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण तथा विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुख फसल विकास योजनाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर क्वालिटी बीजों के उपयोग का प्रचार किया जा रहा है । राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कई अन्य विस्तार एजेंसियों को किसानों को प्रौद्योगिकी अंतरण में नियमित रूप से शामिल किया जाता है।

नेपाली भाषा के विकास हेतु सुविधाएं

*835. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त भाषाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ;

(ख) क्या कुछ संगठनों ने, नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के उपरान्त, इस भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए समान सुविधायें प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत सरकार भाषाओं के विकास में निम्नलिखित के जरिये सहायता प्रदान करती है :

(i) प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान;

(ii) शिक्षण, प्रकाशनों, विचार-गोष्ठियों , अनुसंधान अध्ययनों, इत्यादि सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भाषाओं के प्रचार प्रसार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता ।

(iii) आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को सहायता ।

(ख) और (ग) श्री महेश्वर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) के माध्यम से अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, देहरादून ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें नेपाली भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार का हस्तक्षेप और उनकी सहायता का सुझाव दिया गया है । सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नेपाली अकादमी विभाग को बनाना जहां से नेपाली साहित्य, संस्कृति और कला का प्रचार-प्रसार और विकास किया जा सके ;

(ii) नेपाली लेखकों, कवियों और कलाकारों के प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाये,

(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालयों को असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थापित किया जाना जहां कि नेपाली-भाषी लोग रहते हैं ।

सरकार में नेपाली अकादमी विभाग स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है । साथ ही विभिन्न राज्यों में मंत्रालय के बहुत अधिक कार्यालयों को खोलना व्यवहार्य नहीं समझा गया है । यदि

सरकार की योजना के तहत शिक्षण, प्रकाशनों, विचारगोष्ठियों अनुसंधान अध्ययनों के लिए पात्र स्वैच्छिक संगठन आवेदन करेंगे तो उन्हें उसके लिए सहायता दी जायेगी ।

New High in agricultural performance

*836. DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR: Wilt the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) the New high in Agriculture Performance achieved recently as compared to that in July, 1991;

(b) the indicators of this new high in agricultural performance;

(c) whether India is self-sufficient in Agricultural sector; and

(d) the steps being taken to better the performance in the Agricultural sector?

THE MINISTER OF AGRICULTURE (SHRI BALRAM JAKHAR): (a) New high in agricultural performance was achieved in the production of rice, wheat, total cereals, total foodgrain, Soyabean, Sunflower, Safflower, Rapeseed & Mustard, total oilseeds and cotton during 1994-95 as compared to 1990-91. New high in yield per hectare was also achi-wad during this period for all these crops except Soyabean.

(b) Increase in production and productivity are the key indicators of new high in agricultural performance.

(c) By and large, India is self-sufficient in agricultural sector except for some minor shortages in the production of pulses etc.

(d) In order to increase production and productivity, the following programmes are being implemented:

(i) integrated Cereals Development Prograrnrae-Riee, Wheat & Coarse Cereals.

(ii) National Pulses Development Programme (NPDP).

(iii) Oilseed Production programme (OPP).

(iv) Intensive Cotton Development Programme (ICDP),

(v) Special Jute Development Programme (SJDP).

(vi) Central Sector Mini Kit Programme on Rice, wheat and coarse cereals including propagation of improved crop production technology.

व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के लिए व्यवस्था

*837. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में इस समय व्यावसायिक शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के लिए की गई व्यवस्था आवश्यकता से काफी कम है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि देश में लगभग 235 लाख विद्यार्थी प्रतिवर्ष उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं लेकिन लगभग 4 लाख विद्यार्थियों के लिए ही व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था देश में मौजूद है ;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में तथ्य क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने भविष्य में व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा के विस्तार व विकास हेतु कोई योजना तैयार करने का निर्णय किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत जानकारी क्या है, और देश में वार्षिक रूप से कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था करा पाने का सरकार का लक्ष्य है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) से (ङ) देश में तकनीकी और व्यावसायिक जनशक्ति संबंधी आवश्यकता औद्योगिक गतिविधि के